

खास-खबरें

पारस हेल्थकेयर का आईपीओ लॉन्च, पहले दिन मिला सिर्फ 15 प्रतिशत सब्सक्रिप्शन

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: उत्तर भारत, बिहार और झारखंड में पारस हेल्थ ब्रांड के तहत सुपर स्पेशलिटी केयर और हाईली एडवॉर्ड (क्वाटर्नरी) हेल्थकेयर सेवा देने वाली देश की प्रमुख क्लिनिकल स्पेशलिटी हॉस्पिटल चेन कंपनी पारस हेल्थकेयर लिमिटेड का 1,450 करोड़ रुपये का आईपीओ आज सब्सक्रिप्शन के लिए लॉन्च कर दिया गया। इस आईपीओ में निवेशक 23 अक्टूबर तक बोली लगा सकते हैं।

इश्यू की क्लोजिंग के बाद 26 अक्टूबर को शेयरों का अलॉटमेंट किया जाएगा, जबकि 27 अक्टूबर को अलॉटिड शेयर निवेशकों के डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। इसी दिन रिफंड की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। कंपनी के शेयर 28 अक्टूबर को बीएसई और एनएसई पर लिस्ट हो सकते हैं। पहले दिन का अंत होने तक इस आईपीओ को सिर्फ 15 प्रतिशत सब्सक्रिप्शन मिला था। इस आईपीओ में बोली लगाने के लिए 660 रुपये से लेकर 693 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है, जबकि लॉट साइज 21 शेयरों का है। इस आईपीओ में रिटेल इन्वेस्टर्स कम से कम एक लॉट यानी 21 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें 14,553 रुपये का न्यूनतम निवेश करना होगा। इसी तरह रिटेल इन्वेस्टर अधिकतम 1,89,189 रुपये के निवेश से 13 लॉट में 273 शेयरों के लिए बोली लगा सकते हैं। इस आईपीओ के तहत एक रुपये फेस वैल्यू वाले कुल 2,09,23,520 शेयर जारी किए जा रहे हैं। इनमें लगभग 500 करोड़ रुपये के 72,15,007 नए शेयर जारी किए जा रहे हैं।

ग्लोबल मार्केट से मिले-जुले संकेत एशिया में भी मिला-जुला कारोबार

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: ग्लोबल मार्केट से आज मिले-जुले संकेत मिल रहे हैं। अमेरिकी बाजार पिछले सत्र के दौरान मिले-जुले परिणाम के साथ बंद हुए। वहीं डाउ जॉन्स पयूचर्स आज सुबह मामूली बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार में पिछले सत्र के दौरान बिकवाली का माहौल बना रहा और प्रमुख सूचकांक कमजोरी के साथ लाल निशान में बंद हुए। वहीं एशियाई बाजार में भी आज मिला-जुला कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। यहां कुछ प्रमुख बाजारों में भारी तेजी बनी हुई है, तो कुछ सूचकांक हल्की गिरावट के साथ रिकवरी की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी बाजार में पिछले सत्र के दौरान मिला-जुला रुख दर्ज किया गया, जिसकी वजह से वॉल स्ट्रीट के सूचकांक मिले-जुले परिणाम के साथ बंद हुए। एस एंड पी 500 इंडेक्स ने 21.84 अंक यानी 0.28 प्रतिशत की बढ़त दर्ज करते हुए 7,712.57 अंक के स्तर पर पिछले सत्र के कारोबार का अंत किया। इसके विपरीत टेक-हैवी नैस्डेक कंपोजिट में हल्की बिकवाली देखी गई। यह सूचकांक 6.07 अंक यानी 0.02 प्रतिशत की मामूली गिरावट के साथ 26,424.82 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं डाउ जॉन्स पयूचर्स आज फिलहाल 39.07 अंक यानी 0.07 प्रतिशत की बढ़त के साथ 52,534.95 अंक के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यूरोपीय बाजार में पिछले सत्र के दौरान बिकवाली का माहौल बना रहा, जिससे प्रमुख सूचकांक कमजोरी के साथ बंद हुए। जर्मनी का डीएएक्स इंडेक्स 15.35 अंक यानी 0.06 प्रतिशत की गिरावट के साथ 25,304.42 अंक के स्तर पर बंद हुआ।

त्यौहारों के बावजूद स्मार्टफोन की बिक्री में 26 प्रतिशत गिरावट

दस साल में किसी तिमाही की सबसे कम बिक्री; महंगे होते उपकरण बने प्रमुख वजह

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: त्यौहारों के मौसम में भी भारत में स्मार्टफोन की बिक्री में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। बाजार अनुसंधान संस्था ओमिडिया के अनुसार, जुलाई से सितंबर के बीच देश में 3.58 करोड़ स्मार्टफोन बिके। यह पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 26 प्रतिशत कम है। वर्ष 2016 के बाद किसी एक तिमाही में यह सबसे कम बिक्री है। विशेषणों के अनुसार, स्मार्टफोन की बढ़ती कीमतें और पुराने फोन का लंबे समय तक इस्तेमाल बिक्री घटने के प्रमुख कारण हैं। चिप और अन्य पुर्जों की लागत बढ़ने से कंपनियों को कीमतों में बदलाव करना पड़ा है।

सैमसंग पहले, एपल पांचवें स्थान पर

तीसरी तिमाही में सैमसंग ने 67 लाख फोन बेचकर पहला स्थान हासिल किया। कंपनी करीब ढाई साल बाद फिर शीर्ष पर



पहुंची। उसके किफायती और महंगे फोन की मांग के साथ आसान किस्तों तथा पुराने फोन के बदले छूट देने वाली योजनाओं से बिक्री को सहारा मिला। वीवो 64 लाख फोन बेचकर दूसरे, ओपो 49 लाख के साथ तीसरे और शाओमी 47 लाख फोन की बिक्री के साथ चौथे स्थान पर रही। इन तीनों कंपनियों की बिक्री में क्रमशः 34, 24 और 28 प्रतिशत की गिरावट आई। एपल ने 39 लाख फोन बेचकर पांचवां स्थान हासिल किया।

आईफोन 16 और 17 की मांग तथा आगामी कीमतों में वृद्धि की आशंका के कारण दुकानदारों की ओर से पहले से माल जुटाने से बिक्री को बढ़ावा मिला।

चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी घटी

ओमिडिया के अनुसार, भारतीय स्मार्टफोन बाजार में चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी एक वर्ष पहले के 75 प्रतिशत से घटकर 68 प्रतिशत रह गई। वहीं, सैमसंग और एपल ने अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखी। रिपोर्ट में वर्ष 2027 में भी बाजार में सुस्ती बने रहने की आशंका जताई गई है। हालांकि, लगभग 40 प्रतिशत भारतीय उपभोक्ता उपयोगी कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुविधाओं वाले फोन के लिए अधिक कीमत चुकाने को तैयार हैं, जिससे भविष्य में मांग बढ़ने की उम्मीद है।

भारतीय सेना के लिए 770 करोड़ रुपये में खरीदे जाएंगे उन्नत हल्के रडार

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए उन्नत कम ऊंचाई वाले हल्के रडार खरीदने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ लगभग 770 करोड़ रुपये का अनुबंध किया है। बुधवार को नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इन रडारों की मदद से भारतीय सेना कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई लक्ष्यों का पता लगाने और उनकी निगरानी करने में सक्षम होगी। यह प्रणाली लड़ाकू विमानों के आकार के लक्ष्यों के साथ छोटे और सूक्ष्म ड्रोन का भी पता लगा सकती है। इसमें हवाई लक्ष्यों को प्राथमिकता देने की अतिरिक्त क्षमता भी होगी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इन रडारों की खरीद से भारतीय सेना को मानवहित हवाई प्रणालियों से उत्पन्न खतरों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में सहायता मिलेगी।

स्पेशल खबर

14वां इंडिया केम सम्मेलन, जापान भागीदार देश; जेपी नड्डा करेंगे उद्घाटन...

आज से मुंबई में जुटेंगे वैश्विक रसायन उद्योग के दिग्गज



नईदुनिया ब्यूरो, मुंबई: भारत के रसायन और पेट्रोरसायन उद्योग में निवेश, व्यापार और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 14वें इंडिया केम 2026 का आयोजन 22

से 24 अक्टूबर तक मुंबई के बॉम्बे प्रदर्शनी केंद्र में किया जाएगा। इस तीन दिवसीय कार्यक्रम का विषय 'एडवॉंटेज भारत : एक उभरता हुआ वैश्विक रसायन

केंद्र' रखा गया है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा गुरुवार को इसका उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुग्रिया पटेल भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इस आयोजन का संयुक्त संचालन रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग तथा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ करेंगे। इसमें नीति निर्माता, उद्योग जात के प्रतिनिधि, निवेशक, शोधकर्ता और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ भारत की औद्योगिक क्षमताओं तथा निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे।

जापान भागीदार देश, 100 से अधिक देशों की भागीदारी

आयोजकों के अनुसार, सम्मेलन में जापान, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ के देशों, दक्षिण कोरिया और आसियान देशों सहित 100 से अधिक देशों की भागीदारी की उम्मीद है। जापान इस

बार भागीदार देश के रूप में शामिल होगा। आयोजन में 200 से अधिक भारतीय और विदेशी प्रदर्शक, आठ हजार से अधिक कारोबारी प्रतिनिधि तथा 50 से अधिक प्रमुख मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के शामिल होने की संभावना है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान सहित कई राज्य अपने औद्योगिक संसाधनों और निवेश के अवसरों का प्रदर्शन करेंगे।

2040 तक एक लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचने का अनुमान

भारत वर्तमान में विश्व का छठा सबसे बड़ा और एशिया का चौथा सबसे बड़ा रसायन उत्पादक है। अनुमान है कि भारतीय रसायन उद्योग का आकार वर्ष 2030 तक 300 अरब डॉलर और 2040 तक एक लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच सकता है। बढ़ती घरेलू मांग, निर्यात की

संभावनाएं और सरकारी प्रोत्साहन इस वृद्धि के प्रमुख आधार हैं।

नई तकनीकों और टिकाऊ उत्पादन पर जोर

प्रदर्शनी में विशेष रसायन, उर्वरक, कृषि रसायन, रंग, औद्योगिक प्लास्टिक, कृत्रिम रेशे और पुनर्चक्रित पेट्रोरसायन से जुड़ी तकनीकों का प्रदर्शन होगा। इसके अलावा स्वचालन, रोबोटिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित समाधान, प्रदूषण नियंत्रण, हरित रसायन और जैव-आधारित सामग्री पर भी ध्यान दिया जाएगा।

सम्मेलन में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त उद्यम, अनुसंधान, विनिर्माण और रासायनिक औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश के अवसर तलाशे जाएंगे। आयोजकों का उद्देश्य वैश्विक कंपनियों और भारतीय उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाना, नवाचार को प्रोत्साहित करना तथा भारत की विनिर्माणा क्षमता को मजबूत करना है।

नईदुनिया

जियो आईपीओ के पहले दिन तीन गुना निवेश



पात्र शेयरधारकों के हिस्से में 138 प्रतिशत आवेदन मिले।

कर्मचारियों और शेयरधारकों के लिए आरक्षण

निर्गम में कर्मचारियों के लिए 500 करोड़ रुपये तक के शेयर आरक्षित रखे गए हैं। उन्हें प्रति शेयर 54 रुपये की छूट भी मिलेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के पात्र शेयरधारकों के लिए 2,500 करोड़ रुपये तक का हिस्सा निर्धारित किया गया है। निर्गम में 50 प्रतिशत हिस्सा बड़े संस्थागत निवेशकों, 15 प्रतिशत गैर-संस्थागत निवेशकों और 35

प्रतिशत खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित है। कंपनी ने निर्गम खुलने से पहले 212 बड़े निवेशकों से 8,110 करोड़ रुपये जुटाए थे।

जुटाई गई रकम से चुकाया जाएगा कर्ज

कंपनी के अनुसार, निर्गम से प्राप्त राशि का इस्तेमाल प्रमुख सहायक कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम के कर्ज चुकाने और सामान्य कारोबारी जरूरतों को पूरा करने में किया जाएगा। निर्गम के बाद प्रवर्तकों और प्रवर्तक समूह की हिस्सेदारी 66.43 प्रतिशत से घटकर 64.48 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वहीं, सार्वजनिक शेयरधारिता 33.57

प्रतिशत से बढ़कर 35.52 प्रतिशत हो जाएगी।

देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी

जियो प्लेटफॉर्मस देश की सबसे बड़ी दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी है। 30 जून 2026 तक इसके कुल ग्राहकों की संख्या 53.3 करोड़ थी। इनमें 28.49 करोड़ ग्राहक पांचवीं पीढ़ी की दूरसंचार सेवा का उपयोग कर रहे थे। कंपनी ने 19 जून को निर्गम से संबंधित प्रारंभिक दस्तावेज जमा किए थे और 28 अगस्त को भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड से आवश्यक टिप्पणियां प्राप्त की थीं।

निर्गम से पहले अनौपचारिक बाजार में कंपनी के शेयरों का प्रीमियम 258 रुपये बताया गया था। इसके आधार पर 1,377 रुपये पर सूचीबद्ध होने का अनुमान जताया गया। हालांकि, अनौपचारिक बाजार का प्रीमियम केवल संकेतक है और वास्तविक सूचीबद्धता मूल्य इससे अलग हो सकता है।

भारत और न्यूजीलैंड के बीच इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ों के आदान-प्रदान पर समझौता

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली:भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय व्यापार को सुगम बनाने तथा सीमा शुल्क संबंधी सहयोग मजबूत करने के लिए वस्तुओं के मूल स्थान से जुड़े आंकड़ों के इलेक्ट्रॉनिक आदान-प्रदान पर सहयोग जापान पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पहल दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते के तहत की गई है, जो 20 अक्टूबर 2026 से लागू हो गया है। इस सहयोग जापान पर 19 अक्टूबर को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी और न्यूजीलैंड सीमा शुल्क सेवा की नियंत्रक एवं मुख्य कार्यकारी क्रिस्टीन स्टीवेंसन ने हस्ताक्षर किए। इस व्यवस्था का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार से संबंधित सूचनाओं का सुरक्षित और समयबद्ध आदान-प्रदान सुनिश्चित करना है। इसके माध्यम से वस्तुओं के मूल स्थान से जुड़े आंकड़े इलेक्ट्रॉनिक रूप में पहले ही उपलब्ध हो सकेंगे। इससे सीमा शुल्क प्रक्रियाओं में सहयोग बढ़ेगा



और व्यापार को सुगम बनाने के उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने में सहायता मिलेगी।

व्यापारियों को मिलेगा लाभ

इस पहल से सीमा पार व्यापार की प्रक्रियाओं में दक्षता बढ़ने, सूचनाओं की कमी दूर होने और कारोबारियों को अधिक निश्चितता मिलने की उम्मीद है। दोनों देश

एसबीआई के 3,897 ग्राहकों का आंकड़ा चोरी, बैंक ने शुरू की जांच

बैंक ने कहा- कामकाज और सेवाओं पर असर नहीं



नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के करीब चार हजार ग्राहकों की निजी जानकारी डार्क वेब पर मिलने के बाद बैंक ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बैंक ने बुधवार को शेयर बाजार को दी गई सूचना में बताया कि 3,897 ग्राहक अभिलेखों में व्यक्तिगत पहचान से जुड़ी जानकारीयां पाई गई हैं। बैंक के अनुसार, उसे 16 अक्टूबर को अपने खतरा सूचना सेवा प्रदाता, रक्षा साइबर एजेंसी और भारतीय कंप्यूटर अपातकालीन प्रतिक्रिया दल से इस संबंध में चेतावनी मिली थी। इसके बाद बैंक की तकनीकी टीम ने जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में डार्क वेब पर उपलब्ध लगभग 3.75 लाख अभिलेखों का विश्लेषण किया गया। इनमें ग्राहकों के नाम, लिंग, पंजीकृत मोबाइल नंबर, जन्मतिथि, ईमेल, घर का पता, शाखा कोड, ग्राहक सूचना फाइल पहचान संख्या और ऋण संबंधी अभिलेखों का विवरण शामिल होने की जानकारी सामने आई।

एक अज्ञात हैकर समूह 'सिरियसिम' ने दावा किया था कि उसके पास बैंक के ग्राहकों के आंकड़े, ऋण आवेदन और खाता खोलने से जुड़े दस्तावेज हैं। साइबर सुरक्षा निगरानी खाते 'साइबरपल्स56' ने 16 अक्टूबर को इस दावे को सामाजिक माध्यम पर साझा किया था। हालांकि, चोरी किए गए आंकड़ों की प्रामाणिकता और उनके मूल स्रोत की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। एसबीआई ने बताया कि मामले की जांच के लिए भारतीय कंप्यूटर अपातकालीन प्रतिक्रिया दल से जुड़ी स्वतंत्र साइबर सुरक्षा एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। एजेंसी आंकड़ों के स्रोत और संभावित जोखिमों का आकलन करेगी। बैंक के अनुसार, इस घटना से उसके मुख्य कारोबारी कामकाज, सेवाओं, वित्तीय प्रदर्शन और निरंतर संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। बैंक ने कहा कि मामले पर नजर रखी जा रही है और नियमानुसार आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

‘सिरियसिम’ ने दावा किया था कि उसके पास बैंक के ग्राहकों के आंकड़े, ऋण आवेदन और खाता खोलने से जुड़े दस्तावेज हैं। साइबर सुरक्षा निगरानी खाते ‘साइबरपल्स56’ ने 16 अक्टूबर को इस दावे को सामाजिक माध्यम पर साझा किया था। हालांकि, चोरी किए गए आंकड़ों की प्रामाणिकता और उनके मूल स्रोत की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

एसबीआई ने बताया कि मामले की जांच के लिए भारतीय कंप्यूटर अपातकालीन प्रतिक्रिया दल से जुड़ी स्वतंत्र साइबर सुरक्षा एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। एजेंसी आंकड़ों के स्रोत और संभावित जोखिमों का आकलन करेगी। बैंक के अनुसार, इस घटना से उसके मुख्य कारोबारी कामकाज, सेवाओं, वित्तीय प्रदर्शन और निरंतर संचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। बैंक ने कहा कि मामले पर नजर रखी जा रही है और नियमानुसार आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

के तहत निर्धारित लाभ प्राप्त करने में सुविधा होगी। भारत और न्यूजीलैंड की यह पहल सीमा शुल्क सहयोग को आधुनिक बनाने तथा व्यापार संबंधी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ों के आदान-प्रदान से दोनों देशों के बीच वस्तुओं के व्यापार में प्रक्रियागत बाधाएं कम करने में मदद मिलने की अपेक्षा है।

शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 143 अंक टूटकर 73,710 पर बंद

नईदुनिया ब्यूरो, मुंबई: भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को गिरावट दर्ज की गई। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 143 अंक टूटकर 73,710 पर बंद हुआ। वहीं, निफ्टी 78 अंक गिरकर 22,811 के स्तर पर आ गया। कारोबार के दौरान वाहन, धातु और रियल एस्टेट कंपनियों के शेयरों में अधिक बिकवाली देखने को मिली। इससे पहले 19 अक्टूबर को भी बाजार में गिरावट रही थी। उस दिन सेंसेक्स 876 अंक टूटकर 73,853 पर और निफ्टी 257 अंक गिरकर 22,889 पर बंद हुआ था। दशहरे के अवसर पर 20 अक्टूबर को शेयर बाजार बंद रहा था। जियो प्लेटफॉर्मस का सार्वजनिक निर्गम 21 अक्टूबर को खुला। कंपनी

इसके माध्यम से 30,188 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य लेकर आई है। निवेशक 23 अक्टूबर तक इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। एक आवेदन में न्यूनतम निवेश राशि 13,428 रुपये निर्धारित की गई है।

एशियाई बाजारों में मिला-जुला रुख

एशियाई बाजारों में बुधवार को मिला-जुला कारोबार रहा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी सूचकांक 3.29 प्रतिशत बढ़कर 5,736 पर पहुंचा। जापान का निक्केई 0.85 प्रतिशत की बढ़त के साथ 64,621 पर बंद हुआ। वहीं, हांगकांग का हेंगसेंग 0.90 प्रतिशत गिरकर 23,652 पर

आ गया। अमेरिकी बाजारों में 20 अक्टूबर को भी मिला-जुला रुख रहा। डाउ जॉंस 1.02 प्रतिशत बढ़ा, जबकि नैस्डेक में 0.02 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। एसएंडपी 500 में 0.28 प्रतिशत की बढ़त रही।

विदेशी निवेशकों ने की बिकवाली

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, विदेशी निवेशकों ने पिछले सात दिनों में 5,268 करोड़ रुपये के शेयर बेचे। वहीं, घरेलू संस्थागत निवेशकों ने इसी अवधि में 2,859 करोड़ रुपये की शुद्ध खरीदारी की। बाजार में निवेशकों की गतिविधियों के बीच प्रमुख सूचकांकों में गिरावट दर्ज की गई।

हवाई किराये पर सीधे नियंत्रण नहीं करेगी सरकार

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: केंद्र सरकार हवाई टिकटों के किराये पर सीधे नियंत्रण नहीं करेगी। हालांकि, अपात द्धिकारियों को अत्यधिक किराया देने से बचाने के लिए सरकार के पास दरें तय करने का अधिकार रहेगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार, विमानन कंपनियां मांग और उपलब्ध सीटों के आधार पर किराया निर्धारित कर सकेंगी। नई व्यवस्था के तहत विमानन कंपनियों को उड़ान के किराये की जानकारी एक महीने पहले नागर विमानन महानिदेशालय को देनी होगी। यह जानकारी कंपनियों को अपनी वेबसाइट पर भी उपलब्ध करानी होगी। महानिदेशालय किराये की निगरानी करेगा, ताकि निर्धारित सीमा से अधिक वसूली न हो। इससे पहले केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया था कि विमानन कंपनियों की ओर से मनमाना

किराया वसूलने पर रोक लगाने के लिए दो सप्ताह में नए नियम लागू किए जाएंगे। न्यायालय सामाजिक कार्यकर्ता एस. लक्ष्मीनारायण की याचिका पर सुनवाई कर रहा था। याचिका में त्यौहारों और छुट्टियों के दौरान महंगे टिकटों तथा छिपे हुए शुल्कों पर रोक लगाने की मांग की गई थी। त्यौहारों के दौरान हवाई ईंधन की बढ़ती कीमतों और उड़ानों की सीमित उपलब्धता के कारण टिकट महंगे हुए हैं। विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा था कि विमान ईंधन की कीमतों में वृद्धि के कारण किराये को नियंत्रित रखना चुनौतीपूर्ण हो गया है। सरकार इस संबंध में विमानन कंपनियों और तेल कंपनियों से बातचीत कर रही है। एयर इंडिया ने 9 अक्टूबर से घरेलू उड़ानों पर 1,200 रुपये तक और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर 17,800 रुपये तक अतिरिक्त ईंधन शुल्क लगाने की घोषणा की थी।